POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 04

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अप्रेल, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! वैश्विक मंदी का प्रभाव और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार पर नजर रखते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोक सभा में 2012-13 का आम बजट प्रस्तुत किया। इस बार के बजट से आम लोगों में निराशा अधिक दिखाई दी।

ज्यादातर लोगों का कहना है कि बजट में गरीबों की भलाई और ग्रामीण विकास के सपने तो दिखाए गए हैं। जबकि महंगाई के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का जीना दूभर हो रहा है। ऐसे में बढ़ाए गए सेवाकर और एक्साइज ड्यूटी उनके लिए 'कोढ़ में खाज' वाली कहावत साबित होंगे।

ग्राम गदर के एक पाठक का कहना है कि बजट में विदेशों में जमा कालेधन पर श्वेत-पत्र पेश करने की बात केवल बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन के मद्देनजर की गई है। आमजन को क्या यह जानने का हक नहीं है कि यह धन किन लोगों के नाम से जमा है? यदि यह धन वापस भारत में आ जाए तो टैक्स बढ़ाने के बजाय देश की जनता को कई राहतें दी जा सकती हैं।

ग्रामीण विकास को गति, कृषि को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए शिक्षा व स्वास्थ्य, मिड डे मील, गांवों में स्वच्छ पेयजल जैसी योजनाओं पर बजट में अधिक धन का प्रावधान सराहनीय है। 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि ग्रामीणजन घोषणाओं के सरकारी अमल पर नजर रख सकें और लाभान्वित हो सकें।

समय पर डाक नहीं पहुंचाई, एक लाख 50 हजार का हर्जाना दे

नई दिल्ली निवासी एक छात्रा सईदा मदीहा ने जिला उपभोक्ता मंच, दिल्ली में डाक विभाग के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उसने अपने परिवाद में बताया कि उसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का प्रवेश-कार्ड डाक से आना था, जो कि परीक्षा की तारीख निकल जाने के बाद उन्हें मिला। यह पत्र उन्हें यदि समय पर मिल जाता तो वह प्रवेश परीक्षा देने जा सकती थी और उसका कैरिअर बन जाता, लेकिन डाकघर की लापरवाही से ऐसा नहीं हो सका।

उपभोक्ता मंच में मामले की सुनवाई पर डाक विभाग की ओर से कहा गया कि विभाग इस मामले को लेकर खुद उलझन में है और इस बात की जांच करवा रहा है कि प्रवेश कार्ड छात्रा तक समय पर क्यों नहीं पहुंचा। डाक विभाग की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि छात्रा का पता गलत था, किसी तरह पता लगाकर डाक सुपुर्द की गई थी। लेकिन यह तर्क सिद्ध नहीं हो पाया। उपभोक्ता मंच ने समय पर डाक नहीं पहुंचाने को गंभीर लापरवाही के दायरे में लिया और डाक विभाग को आदेश दिया कि वह छात्रा सईदा को एक लाख 50 हजार रुपए का हर्जाना अदा करे।

महानरेगा योजना की कमियों को दूर करना आवश्यक

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य एवं राजस्थान योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो. वी.एस.व्यास ने कहा है कि महानरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है। पूरे विश्व में इस तरह की रोजगार देने वाली योजना नहीं है, जिसमें 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित किया गया हो। उन्होंने योजना में आने वाली बाधाओं और विफलताओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि समय पर यदि योजना के क्रियान्वयन में सुधार नहीं लाए गए तो यह योजना दम तोड़ देगी।

उन्होंने उक्त विचार 'कट्स'द्वारा 14 मार्च को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार एवं पैरवी बैठक में मुख्य अतिथि रूप में व्यक्त करते हुए योजना में सुधार के लिए कई सुझाव दिए।

बैठक में राज्य विधानसभा सदस्य राव राजेन्द्र सिंह, प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एम.एल.मेहता, इन्स्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज के निदेशक सुरजीत सिंह और कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने भी योजना में रही कमियों पर अपने विचार रखते हुए योजना के क्रियान्वयन में सुधार व सुशासन के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव रखे। कार्यक्रम में सरकारी विभागों व मीडिया प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के सभी जिलों के 66 स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जमीनी स्तर तक पहुंचे वित्तीय अधिकारों की जानकारी

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर 'कट्स' द्वारा 16 मार्च 2012 को 'हमारा पैसा हमारे अधिकारः वित्तीय सेवाओं में उपभोक्ता संरक्षण' विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय जयपुर की उपमुख्य प्रबन्धक श्रीमती के. सुन्दरी ने बैंकिंग लोकपाल और भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली और वित्तीय सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अब ग्रामीण जनमानस को बैंकों से जोड़ने के लिए तेज प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार के प्रवर्तन अधिकारी संजय झाला ने उपभोक्ताओं को बेहद सावधानी से अपना धन निवेश करने व लेन-देन करने का सुझाव दिया। कार्यशाला में विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों ने उपभोक्ता हितार्थ कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में कट्स निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज भी उपभोक्ताओं का एक बड़ा समुदाय बैंकों और वित्तीय सुविधाओं से वंचित है और वे अपने अधिकारों से वाकिफ तक नहीं हैं। कार्यशाला में स्वयंसेवी संस्थाओं व मीडिया के करीब 70 प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लिया।

किसानों व खेती-बाड़ी को खास तबज्जो

केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिक दर्जा दिया है। खेती में तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर दिया जाएगा। कृषि उपकरणों, उनके पुर्जों और उर्वरक परियोजनाओं के विस्तार व स्थापना के लिए बुनियादी सीमा शुल्क को कम किया गया है।

किसानों को फसलों के लिए सही समय पर कर्ज मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4 फीसदी पर कर्ज की योजना को बरकरार रखा गया है। कृषि उत्पादों के सही भंडारण के लिए उन्हें फसल के बाद के ऋणों पर भी 3 प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। कृषि का बजट 18 फीसदी बढ़ाकर 20 हजार 208 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे किसानों के लिए कई नई राहें खुलेंगी। किसान कार्ड अब स्मार्ट कार्ड में बदले जाएंगे जिनका एटीएम में भी उपयोग किया जा सकेगा।

चिकित्सा और पेयजल पर ज्यादा ध्यान

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं पीने का साफ पानी मुहैया कराने पर खास ध्यान दिया है। गांवों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था के लिए पिछले साल से 27 फीसदी से भी अधिक, 14 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

साथ ही दूरदराज के गांवों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के मकसद से पिछले बजट के मुकाबले 20 फीसदी धनराशि बढ़ाकर 20 हजार 822 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुपोषण की रोकथाम के लिए गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलने वाले कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाया जाएगा।

गरीबों को मकान के लिए कर्ज

देश के महानगरों, कस्बों और गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को मकान के लिए बजट में ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इसके लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट निधि की स्थापना होगी। इस निधि से आवश्यकता होने पर बैंकों को ऋण देने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

बीपीएल परिवारों को संकट के दौर से उबारने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीपीएल परिवार के 18 से 64 वर्ष के प्रमुख सदस्यों की मृत्यु पर मिलने वाली 10 हजार रुपए की अनुदान राशि को दोगुना यानि 20 हजार रुपए कर दिया गया है।

गांवों के विकास को प्राथमिकता

ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय बजट में 74 हजार 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गांवों में सड़कें बनाने पर 24 हजार करोड़, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था और शौचालय बनाने के लिए 14 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। महानरेगा के तहत 3915 करोड़ रुपए आजीविका मिशन पर खर्च किए जाएंगे।

देश में स्वाभिमान अभियान के तहत 31 मार्च 2012 से पहले 73 हजार बस्तियों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 1278 करोड़ रुपए खर्च किया जा सकेगा। सर्वशिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण स्कूलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर

पिछले बजट में महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि का सृजन किया गया था। इस निधि को बढ़ाकर अब 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। समूहों को सात प्रतिशत सालाना दर से तीन लाख रुपए तक के ऋण के रूप में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। समय पर ऋण चुकाने पर तीन फीसदी ब्याज माफ हो जाएगा।

इस ऋण से समूह की महिलाएं कोई व्यवसाय खोल कर आत्मनिर्भर हो सकेंगी। विधवा व निशक्त जन पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है लेकिन इससे उन्हें कोई सुकून मिलता नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 'आशा' का मेहनताना बढ़ाने की भी बात की गई है।

खाद्य सुरक्षा एक कानूनी हक

केन्द्र सरकार ने सभी लक्षित लोगों, विशेषकर गरीब और दुर्बल वर्गों के लिए भोजन को एक कानूनी हक बनाते हुए पूरे परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 संसदीय समिति के समक्ष है।

इस विधेयक के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए यूआईडी-'आधार' प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र सृजित किया गया है।

लोगों तक नकद सब्सीडी, विधवा, निशक्तता पेंशन व छात्रवृति आदि के भुगतान में भी इस प्रणाली का उपयोग होगा और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे राशि जमा हो सके ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

नेताओं का निजी स्वार्थ

बढ़ते भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, महंगाई और मिलावट से देश का हर व्यक्ति परेशान है। इन्हें रोकने में सरकारें असफल साबित हो रही है। क्योंकि सरकार में कई जनप्रतिनिधि निजी स्वार्थ को ज्यादा अहमियत देते हैं। विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत वापस लाने की काफी अर्से से मांग उठ रही है।

बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के अन्दोलन को ऊंचे सिंहासनों पर बैठे राजनेताओं ने किस तरह विफल किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि अधिकतर काला धन इन्हीं राजनेताओं का है। इसी वजह से आज तक कालाधन किसका, नाम उजागर नहीं हो रहे। यह कालाधन अगर देश में वापस आ जाए तो बजट में टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे और देश से गरीबी खत्म हो सकेगी।

- भवानी शंकर शर्मा, सुजानगढ़

देशभर की पंचायतें होंगी मजबूत

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से देशभर में पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए बजट में एक बड़े कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत क्षमता निर्माण के लिए मौजूदा योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा है कि महानरेगा योजना का ग्रामीण आजीविका सुरक्षा पर काफी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। इससे सामुदायिक सम्पत्तियां बनी है। ग्रामीण विकास के मद्देनजर विकास योजनाओं में जरूरी सुधार किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण जनता ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके।

'मिड-डे-मील' से मिली सफलता

स्कूलों में दोपहर का भोजन अर्थात मिड-डे-मील के लिए बजट में इस साल 11हजार 937 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बों में यह परियोजना काफी प्रभावी रही है। इससे स्कूलों में नांमाकन बढ़ा है और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने में भी सहायक है।

इस सफलता को देखते हुए बजट में वृद्धि की गई है। हालांकि मिड-डे-मील की गुणवत्ता और तैयारी को लेकर काफी शिकायतें आती हैं। वित्त मंत्री ने भोजन की गुणवत्ता में सुधार किए जाने पर बल दिया है। देश में दौ सौ जिलों में किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए 'सबला' योजना के लिए भी 750 करोड़ रुपए आंवटित किए गए हैं।

'कट्स' की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन

राज्य सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं से बजट पूर्व परामर्श के दौरान कट्स द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं व अनुसंधान कार्यों के अनुभवों के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही योजनाओं में सुधार कर राज्य की विकास दर को बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।

ज्ञापन में महानरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, निशुल्क दवा योजना, विकलांगों की योजनाओं एवं सूचना का अधिकार सम्बन्धित कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए, सुधार के लिए उठाए जाने योग्य कदमों पर ध्यान आकर्षित किया गया है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485